खबरों में रहे स्टॉक

जेएसडब्लयू इन्फ्रास्ट्रक्चर

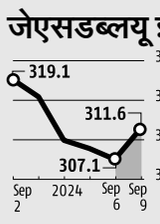

जयगढ़ और धरमतार बंदरगाह पर क्षमता विस्तार के लिए 2,359 करोड़ का व्यय मंजूर

₹ 307.1 पिछला बंद भाव
₹ 311.6 आज का बंद भाव
1.5 % ▲

ग्रीव्स कॉटन

दोपहिया के लिए ईएमपीएस योजना प्रोत्साहन के लिए मिली सरकार की मंजूरी

₹ 165.3 पिछला बंद भाव
₹ 175.5 आज का बंद भाव
6.1 % ▲

आईसीआईसीआई प्रू. ला. इंश्योरेंस

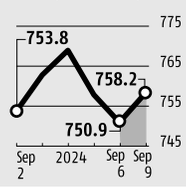

नया कारोबारी प्रीमियम पिछले साल के मुकाबले 24 प्रतिशत बढ़ा

₹ 750.9 पिछला बंद भाव
₹ 758.2 आज का बंद भाव
1.0 % ▲

रॉयल आर्किड होटल्स

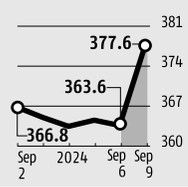

नेपाल के चितवन में की नये रिसॉर्ट रीजेंटा रिसॉर्ट ऐंड स्पा की शुरुआत

₹ 363.6 पिछला बंद भाव
₹ 377.6 आज का बंद भाव
3.9 % ▲

तिलकनगर इंडस्ट्रीज

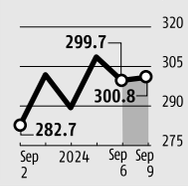

निदेशक मंडल ने स्पेसमैन स्पिरिट्स लैब में निवेश को मंजूरी दी

₹ 299.7 पिछला बंद भाव
₹ 300.8 आज का बंद भाव
0.4 % ▲

संक्षेप में

ग्लास ट्रस्ट को शायद कोई पैसा न मिले : बैजू

थिंक ऐंड लर्न को हो सकता है कि विवादित 1.2 अरब डॉलर के सावधि ऋण 'बी' के लिए किसी राशि का भुगतान न करना पड़े। बैजूस ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी को यह राशि ग्लास ट्रस्ट को चुकानी है, जो अमेरिकी स्थित ऋणदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी बैजू रवींद्रन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिवाला समाधान पेशेवर (आईआरपी) के अनुसार बैजूस पर सत्यापित ऋण दावा अब केवल 20 करोड़ रुपये है। ग्लास ट्रस्ट ने बायजू के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें 1.35 अरब डॉलर या 11,432.98 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा किया गया है। ग्लास ट्रस्ट का कहना है कि शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म ने अमेरिका स्थित ऋणदाताओं से सावधि ऋण 'बी' (टीएलबी) के रूप में 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर लिए थे। ब्याज मिलाकर बकाया राशि बढ़ गई है। *भाषा*

जीएमआर समूह फ्रापोर्ट से लेगा 10 % हिस्सेदारी

जीएमआर समूह की हवाई अड्डा कारोबार इकाई ने फ्रापोर्ट एजी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड के साथ शेयर खरीद समझौता किया है जिसके तहत वह दिल्ली इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी 12.6 करोड़ डॉलर में खरीदेगी। जीएमआर एयरपोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीआईएल) ने सोमवार को बयान में कहा कि यह सौदा पूरा होने के बाद संयुक्त उद्यम डायल में उसकी हिस्सेदारी 64 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत हो जाएगी। *भाषा*

रसोई-घरेलू उपकरण क्षेत्र में उतरी देवू

दक्षिण कोरियाई ब्रांड देवू ने भारत में रसोई तथा घरेलू उपकरण खंड में उतरने की सोमवार को घोषणा की। कंपनी का लक्ष्य बढ़ते भारतीय बाजार में मौजूद अवसरों को भुनाना है। घरेलू बाजार में पिछले साल प्रवेश करने वाली कंपनी एलईडी टीवी, आईएफपी एलईडी टीवी, अल्कलाइन और बैटरी इन्वर्टर जैसे उत्पाद बनाती है। *भाषा*

एक्मा के 64वें सालाना सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ...

'ईवी की लागत घटी, पर सब्सिडी पर फैसला लेने वाला मैं नहीं'

ध्रुवाक्ष साहा
नई दिल्ली, 9 सितंबर

इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ बढ़ाने के लिए सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं बताने वाले बयान के कुछ दिन बाद आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि यह उनके निजी विचार थे, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी का आधिकारिक निर्णय लेने वाले वह कोई नहीं हैं।

गडकरी ने ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एक्मा) के 64वें सालाना सत्र में कहा, 'मैं किसी प्रोत्साहन के खिलाफ नहीं हूं। भारी उद्योग मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है और अगर उसकी इच्छा और अधिक प्रोत्साहन देने की है तो मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं है। मेरा बस यही कहना है कि जब इलेक्ट्रिक वाहन आया था तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत 150 डॉलर प्रति किलोवॉट प्रति घंटे थी। अब, यह करीब 108 से 110 डॉलर है और मुझे पूरा भरोसा है यह कम होकर 100 डॉलर हो जाएगा। इस आधार पर मुझे लगता है कि बगैर सब्सिडी के भी लागत बरकरार रखी जा सकती है क्योंकि उत्पादन खर्च कम हो गया है।'

गडकरी ने कहा, 'अगले दो वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन की लागत पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों जितनी ही हो जाएगी। उन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं है क्योंकि ईंधन के तौर पर बिजली का लाभ उन्हें पहले से ही मिल रहा है। फिर भी अगर वित्त मंत्री और भारी उद्योग मंत्री और अधिक सब्सिडी देना चाहते हैं, तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा।'

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच यात्री वाहनों के लिए करीब 2 फीसदी और वाहन श्रेणियों में 6 फीसदी है। जीवाश्म ईंधन वाली अर्थव्यवस्था के कट्टर आलोचक माने जाने वाले गडकरी ने इस मुद्दे पर भी अपना रुख स्पष्ट किया मगर उन्होंने यह भी कहा कि जीवाश्म ईंधन की बढ़ती खपत उनके लिए एक समस्या है।

मंत्री ने कहा, 'सबसे पहले तो मैं पेट्रोल, डीजल अथवा जीवाश्म ईंधन का विरोधी नहीं हूं। कई बार मेरी बातों का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। मगर हमारे पास जीवाश्म ईंधन के आयात के लिए 22 लाख करोड़ रुपये का बिल है। क्या यह देश के लिए चुनौती नहीं है? देश में 40 फीसदी वायु प्रदूषण परिवहन क्षेत्र के कारण होता है और मैं मंत्री के तौर पर इसके लिए जिम्मेदार भी हूं। क्या यह सही है?' उन्होंने कहा, 'मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जैव ईंधन में आर्थिक व्यवहार्यता और एक अच्छा बाजार भी है। फिर भी आप पेट्रोल-डीजल पर ही जोर क्यों देते हैं?'

वाहन कबाड़ पर मिले ज्यादा छूट

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर वाहन विक्रेताओं द्वारा नए वाहनों पर दी जाने वाली छूट बढ़ाई जानी चाहिए पूछने पर गडकरी ने कहा कि उद्योग और अधिक कर सकता है। उन्होंने कहा, 'मुझे किसी से आग्रह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर कोई बाजार पर कब्जा करना चाहता है और प्रतिस्पर्धा है। उसके लिए, कोई विकल्प नहीं है। उन्हें छूट बढ़ानी होगी चाहे वे इसे पसंद करते हों या नहीं करते हों। वे समझदार लोग हैं, उन्हें कारोबार की समझ है। इसलिए, वे अपनी छूट को बढ़ाएंगे।'

उन्होंने मौजूदा कबाड़ परिदृश्य की तुलना विमानन कंपनियों के शुरुआती दिनों की, जहां प्रतिस्पर्धी विमानन कंपनियों बड़ी छूट की पेशकश की थी, जिससे अंततः उपभोक्ताओं को ही फायदा हुआ।

उत्पादन बढ़ाएं, आयात कम करें वाहन कलपुर्जा विनिर्माता : गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को भारतीय मोटर वाहन कलपुर्जा विनिर्माताओं से आयात पर निर्भरता कम करने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के तरीके तलाशने को कहा, ताकि देश इन उत्पादों का शुद्ध निर्यातक बन सके। मंत्री ने इन कंपनियों से 2030 तक 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखने का भी आग्रह किया।

वाहन कलपुर्जा उद्योग को संबोधित करते हुए उन्होंने विदेशी आपूर्ति पर निरंतर निर्भरता पर चिंता व्यक्त की तथा घरेलू विनिर्माताओं को स्थानीय उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा 'हमारे कई कलपुर्जा विनिर्माता अब भी दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और किसी पड़ोसी देश से कच्चे माल की आवश्यकता के कारण आयात करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा किसी मजबूरी के कारण होता है या स्वेच्छा से।' गोयल ने कहा कि विशाल भारतीय बाजार और वैश्विक अवसरों के साथ उद्योग वर्ष 2030 तक निर्यात को वर्तमान 21.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचा सकता है। मंत्री ने कहा कि सरकार 20 स्मार्ट औद्योगिक शहरों का विकास कर रही है, जिनमें उद्योगों के लिए आवश्यक संपूर्ण परिवेश होगा तथा कलपुर्जा क्षेत्र इन औद्योगिक टाउनशिप में अवसरों की तलाश कर सकता है। *भाषा*

फेम-3 शुरू होने तक जारी रहेगी ईएमपीएस योजना

नितिन कुमार
नई दिल्ली, 9 सितंबर

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) को फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम-3) के तीसरे चरण की शुरुआत होने तक बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित 64वें एक्मा वार्षिक सत्र के दौरान कहा, 'फेम के शुरू होने तक इसका विस्तार किया जाएगा।' ईएमपीएस 30 सितंबर को समाप्त होने वाली है। यह विस्तार दो महीने के लिए होने की संभावना है। एक्मा भारत की ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है।

पिछले सप्ताह कुमारस्वामी ने संकेत दिया था कि फेम-3 अगले दो महीने के भीतर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा था, 'सरकार स्थानीय विनिर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के ईवी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फेम-3 की शुरुआत दो महीने के भीतर की जाएगी।'

अगर ऐसा होता है तो यह ईएमपीएस के लिए दूसरा विस्तार होगा जिसे शुरुआत में 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चार महीने के लिए शुरू किया गया था और इसके लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए थे। योजना की शुरुआती अंतिम समयसीमा से पहले ही इसे दो महीने पहले तक बढ़ा दिया गया था जिससे इसकी आवंटित राशि बढ़कर 778 करोड़ रुपये हो गई। बिजनेस स्टैंडर्ड खबर दे चुका है कि 15 अगस्त तक ईएमपीएस अपने संशोधित लक्ष्य का 60 प्रतिशत पूरा कर चुकी है और 5,60,000 ईवी के लक्ष्य में से 3,34,260 वाहनों को सहायता दी गई है।

214 करोड़ रुपये या आवंटित राशि 778 करोड़ के 27 प्रतिशत के लिए दावे पेश किए गए हैं। यह राशि पिछले व्यय से इस्तेमाल किए गए पैसा का 42 प्रतिशत से अधिक है। एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, काइनेटिक, रिवोल्ट, महिंद्रा और पियाजियो जैसी प्रमुख मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) इस योजना की प्रमुख भागीदार हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय एक ऐसी योजना की रूपरेखा भी तैयार कर रहा है जिसके तहत सब्सिडी योजना के तहत बेचे जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पर मंत्रालय का लोगो होगा और साथ ही ग्राहकों को इस योजना के बारे में जानकारी देने वाला प्रमाण पत्र भी।

इसके अलावा सरकार खुद से की जाने वाली केवाईसी प्रक्रिया भी अनिवार्य कर सकती है, जिसके तहत ग्राहक के लिए अपना वाहन पंजीकृत कराने के लिए सरकारी पोर्टल पर एक सेल्फी अपलोड करना और अपने आधार विवरण प्रमाणित करना जरूरी होगा।

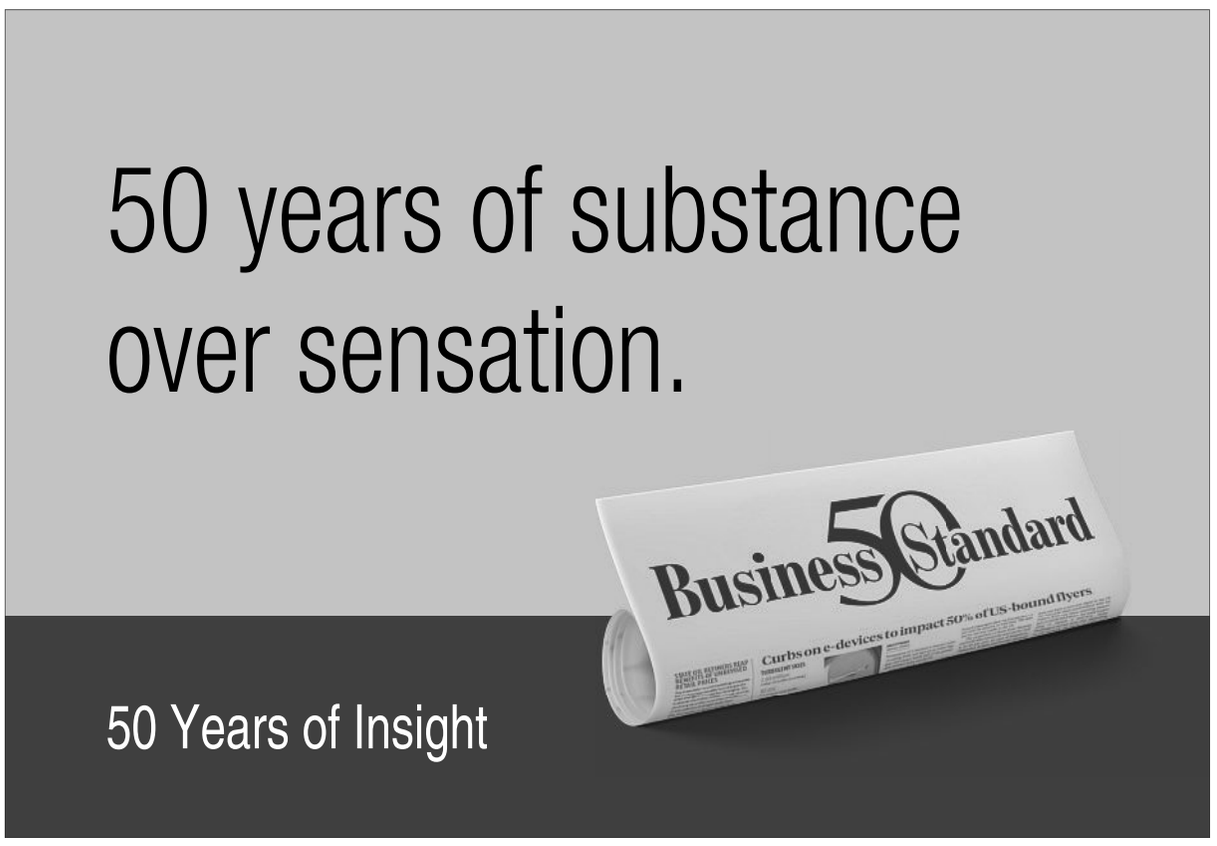

e-Tender Notice

The Executive officer, Bhagwangola – I Panchayet Samiti invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafide outsiders for NIeT No. **06/15th CFC/Bgola-I** Date of publication of e-NIT: 05/09/2024 at 14.00 hrs, Last date of submission of bid (online): 18/09/2024. At 14.00 hrs For more details, please contact with the office of the undersigned or visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive officer, Bhagwangola – I Panchayet Samiti

12/BDO/MDW/2024-25, Dt. 09/09/2024

Block Development Officer, Nabagram Development Block invites e-tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for for mentioned work. Website - **htpp://wbtenders.gov.in.** Tender Id: **2024_ZPHD_747384_1 for NIeT. No. 12/BDO/MDW/2024-25, Dt. 09.09.2024.** Details information is available at the website and office of the undersigned on any working days.

Date: 09/09/2024
Place Nabagram

Sd/-
Block Development Officer Nabagram Development Block

हावड़ा नगर निगम
4, महात्मा गाँधी रोड, हावड़ा - 711 101
दूरभाष 033 2638 3211/12/13 फैक्स: 033 2641 0830, हमसे मिलें www.myhmc.in

सफाई विभाग
संक्षिप्त निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, हावड़ा नगर निगम द्वारा नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदादाताओं को वैध पैन कार्ड, जीएसटी, पीटी., आईटीआर, ट्रेड लाइसेंस एवं अनुशंसापत्र के साथ प्रस्ताव जमा करना होगा।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा सं. एवं तारीख
01	एचएमसी वार्ड नं. 14, 18, 19, 45, (46 व 47), (45 व 38), 8, (6 व 7) 34, (1, 2, 3, 4, 5, 6 व 11), (17, 18 व 29), 41, (24, 25 व 27) के अधीन विभिन्न स्थानों पर ड्रेनों का निर्माण व नवीनीकरण, एक वर्ष हेतु संचालन एवं रखरखाव तथा गाद निकालने का कार्य।	सं. 008/कन्स/24-25 दिनांक 07/09/2024
02	महेन्द्र भट्टाचार्जी रोड से बैलेसिंग रिजर्वर (पद्मपुकुर जोला) तक हावड़ा कैनल का नवीनीकरण।	सं. 009/कन्स/24-25 दिनांक 07/09/2024

बोली जमा (ऑनलाइन) करने की अंतिम तारीख: 26.09.2024 को अपराह्न 5.00 बजे तक।
कृपया **https://wbtenders.gov.in** देखें।
आर्डर सं. : 56(3)/24-25 दिनांक: 09.09.2024

कार्यपालक अभियंता
हावड़ा नगर निगम

नोएडा में आइकिया लगाएगी 5,500 करोड़ रुपये

वीरेंद्र सिंह रावत और एजेंसी
लखनऊ, 9 सितंबर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में 5,500 करोड़ रुपये की आइकिया स्टोर परियोजना की आज आभासी रूप से आधारशिला रखी। इंग्का सेंटर्स, जो आइकिया रिटेल ब्रांड का परिचालन करने वाले इंग्का ग्रुप का हिस्सा है, ने लाइकली ब्रांड के तहत नोएडा में भारत में अपना दूसरा मीटिंग प्लेस स्थापित करने के लिए 5,500 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

इस अवसर पर योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों दोनों का ही विश्वास हासिल किया है। उन्होंने आइकिया इंडिया को इसका ताजा उदाहरण बताया। इंग्का सेंटर्स की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एक आइकिया रिटेल स्टोर, एक होटल, कार्यालय स्थल, एक शॉपिंग सेंटर वगैरह शामिल होंगे।

उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है जो वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था में 9.2 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है, जो भारत के विकास के वृद्धि इंजन के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।' उत्तर प्रदेश में आइकिया इंडिया के 5,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को महत्त्व देते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में भारत में पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। इस पूरी परियोजना से 9,000 से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार पैदा होने और इस क्षेत्र में राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कंपनी के वैश्विक विस्तार एवं विकास निदेशक सेबेस्टियन हाइलिंग ने बताया कि इसके साथ देश में कंपनी का कुल निवेश एक अरब यूरो हो जाएगा। इंग्का सेंटर्स भारतीय बाजार पर बड़ा दांव लगा रही है और विस्तार पर मंथन कर रही है। आइकिया की देश में अपने बिक्री केंद (आउटलेट) खोलने की योजना है। हालांकि गुरुग्राम में इसके पहले (मीटिंग प्लेस) लाइकली गुरुग्राम के उद्घाटन को 2025 अंत से अब 2026 तक टाल दिया गया है।

सेबेस्टियन हाइलिंग ने कहा 'इसमें (लाइकली नोएडा में) 60.7 करोड़ यूरो का निवेश किया जाएगा। यह निवेश पूरी तरह से नोएडा परियोजना के लिए है। फिर हमारे पास जीएमपी (गुरुग्राम मीटिंग प्लेस) के लिए भी निवेश है। इसलिए मुझे लगता है कि पहली दो परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर यह करीब एक अरब (यूरो) है और हमें नहीं लगता कि यह इन दो केंद्रों तक ही सीमित रहेगा।'

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय :–9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली–110001 फोन:–011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइट : www.pnbhousing.com**
जमशेदपुर शाखा: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बढ़ानी ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, आर. रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर–831001, झारखंड।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्यभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल) /प्रत्यभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है"**, **जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामत: **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/TATA/0918/584362, बी.ओ. जमशेदपुर.नीरज कुमार पांडे, श्रीमती संध्या कुमारी	**09.07.2021 तक रु. 2907586.82**	**भौतिक कब्जा**	वह सभी आवासीय फ्लैट फ्लैट नं. 02, प्रथम तल पर, 1240 वर्ग मीटर में फैले हुए हैं। फीट सुपर बिल्ड अप एरिया, गोकुल टॉवर, के रूप में जानी जाने वाली इमारत में, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मैंगो, टाउन जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, एक कार पार्किंग स्थल के साथ–साथ 0.41 डेसीमल मापने वाले गृहस्थी भूमि क्षेत्र के अविभाजित आनुपातिक हिस्से पर अधिकार के साथ, पुराने खाता नंबर 25 के तहत दर्ज, पुराना प्लॉट नंबर 207, 208 और 209, नए खाता नंबर 325 के अनुरूप, नए प्लॉट नंबर 977/5030 का हिस्सा, साथ ही सभी अधिकार शीर्षक, लाभ, विशेषाधिकार और सामान्य सेवाएं, आम सड़कों, गलियों के रास्ते आदि का उपयोग करके प्रवेश और निकास का अधिकार मौजा पारडीह, थाना: मानगो, थाना नंबर 1641, वार्ड नंबर 9 एमएनएसी, के साथ जिला उप–रजिस्ट्री कार्यालय अंचल और टाउन जमशेदपुर, परगना धालभूम और जिला पूर्वी सिंहभूम और झारखंड राज्य के अंतर्गत स्थित है और संपत्ति शाखा रोड पर। संपत्ति इस प्रकार से जुड़ी हुई है और इसकी सीमा इस प्रकार है: – उत्तर में खुले आसमान से, दक्षिण में फ्लैट नंबर 01 से, पूर्व में खुले आसमान से, पश्चिम में पैसेज सीढ़ी और लिफ्ट से।	रु. 3426000	रु. 342600	14.10.2024	रु. 10,000	03.10.2024. अप. 10.00 बजे पूर्वा. 5.30 बजे	15.10.2024. पूर्वा. 12.30 बजे पूर्वा. 2.30 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकरी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।

1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है।
2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(सी) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।
4. **मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता: प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट – **www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी
मुकेश विश्नोई संपर्क नंबर 1800 120 8800, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखे

स्थान: जमशेदपुर, दिनांक: 10-09-2024 **प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

BURDWAN MUNICIPALITY
Amrut Department
NIT No.- 01/2024-2025 (2nd call)
Memo No.- 251/III/A-2.0/3/3/1/2024/ NIT-1/24-25/V1 Date 06.09.2024

Waterbody Rejuvenation of "Shyam Sayer" at Ward No. 30 & 32 wihtin the Burdwan Municipality under AMRUT 2.0. Tender ID : 2024_MAD_746957_1. **Last Date of Submission 01.10.2024**. For details visit: **www.burdwanmunicipality.gov.in**

Sd/-
Chairman
Burdwan Municipality

e-Tender Inviting Notice

Construction of Single Storied Anganwari Center no.-83 at mouza-Jesua JL no.-239, Plot no.-147 within Khanamohan GP under Debra Dev. Block.
e-N.I.T. No.: 09 of 2024-25 (Memo No.- 4099/BDO-Deb, Dated-09.09.2024)
Last Date & Time of submission tender documents : 24.09.2024 upto 17:00 hrs.
Details may be had from the office in official date & time & **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Block Development Officer
Debra Development Block

कोलकाता संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जय हरगोविंददास सरैया द्वारा सरस्वती प्रिंट फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड, 789, चौभागा वेस्ट, पोस्ट ऑफिस–तिलजला, कोलकाता–700105, प. बंगाल से मुद्रित एवं बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, सी/ओ एपीजे बिजनेस सेंटर, 15 पार्क स्ट्रीट, एपीजे हाउस, ब्लॉक–सी, 8वां तक, कोलकाता 700016, प. बंगाल से प्रकाशित। संपादक : कैलाश नौटियाल आरएनआई नं. WBHIN/2008/24333 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन – 033–22101314/1022/1600 फैक्स – 033–22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं